प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 1 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 27 – 03 जनवरी 2022 मूल्य पांच रूपए

प्रधानमंत्री की मंडी यात्रा से हिमाचल को क्या मिला पूछा जाने लगा है यह स्वाल

- क्या 35 किलो का त्रिशूल भेंट करने और काशी विश्वनाथ में की पूजा का आपस में संबंध है
- अभी तक संगठन और सरकार में नहीं हो पाया कोई बदलाव

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मण्डी यात्रा से प्रदेश और भाजपा सरकार को क्या हासिल हुआ है। यह स्वाल अब प्रशासनिक तथा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि मण्डी आयोजन के अवसर पर यह उम्मीद थी कि कर्ज के चक्रव्यूह में लगातार फंसते जा रहे प्रदेश को इससे उबारने के लिए प्रधानमंत्री कोई आर्थिक सहायता देकर जायेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। डबल ईंजन की सरकार का दम भरने वाली जयराम सरकार को इस अवसर पर निराशा क्यों हाथ लगी यह बड़ा सवाल बन गया है। जय राम सरकार ने शिव की संज्ञा से संबोधित हो चुके नरेंद्र मोदी को 35 किलो के वजन का अष्ट धातु से निर्मित त्रिशूल भी भेंट किया लेकिन मोदी फिर भी नहीं पसीजे। यह अलग बात है कि इस त्रिशूल को मोदी मंच पर हाथ में उठाकर जनसमूह को लहरा कर बता नहीं पाये। वैसे कुछ लोग इस त्रिशूल प्रकरण को काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में प्रधानमंत्री द्वारा की गयी पूजा – अर्चना के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं। चर्चा है कि यहां पर जिस पंडित ने प्रधानमंत्री से यह पूजा – अर्चना करवायी है वह पंडित उस दिन इस पूजा का अधिकारी ही नहीं था। क्योंकि उस दिन वह स्वयं पातक का दोषी था। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार सूतक और पातक से ग्रस्त व्यक्ति के लिए ऐसे काल में पूजा – अर्चना करना तो दूर बल्कि ऐसा व्यक्ति ऐसे समय में मंदिर में प्रवेश करने का भी अधिकारी नहीं होता है।

लेकिन पंडित ने इसका ध्यान न रखकर प्रधानमंत्री से यह पूजा करवा दी। इस आधिकारिक प्रयास की शिकायत काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व न्यासी प्रदीप कुमार बजाज ने पी.एम.ओ. और हिमाचल यूके एक न्यूज़ पोर्टल से की है। शिकायत में यह कहा गया है कि ऐसी ही गलती पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी से कमलापति त्रिपाठी ने करवायी थी। इस शिकायत पर भी पी.एम.ओ. द्वारा शायद जांच भी आदेशित हो चुकी है। ऐसे में ज्योतिष और तंत्र के ज्ञाता जब इन दोनों प्रसंगों को एक साथ जोड़ कर देख रहे हैं। तो उनकी प्रतिक्रियाएं सब इस संदर्भ में काफी गंभीर हो रही हैं। यह एक संयोग घटा है कि हिमाचल के मण्डी आयोजन से पहले काशी विश्वनाथ का प्रसंग घट गया और मण्डी में 35 किलो के वजन का त्रिशूल हाथ से नहीं उठाया गया। अब इस सबका प्रदेश और जयराम सरकार पर भी कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है या नहीं यह एक अलग चर्चा का विषय बना हुआ है। हिमाचल को प्रधानमंत्री अपनी यात्रा में कुछ देकर नहीं गये हैं यह सामने है। इसी के साथ यह भी सामने है कि उपचुनावों में हुई शर्मनाक हार के बावजूद सरकार और संगठन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री के मण्डी आगमन से पहले मुख्यमंत्री ने एक साक्षात्कार में यह दावा किया था कि सरकार और संगठन में कुछ बदलाव अवश्य हो गये हैं और इस संबंध में हाईकमान से बात कर ली गयी है। लेकिन मुख्यमन्त्री के इस दावे के बावजूद अभी तक कोई बदलाव हो नहीं पाया है।

इसी पूरी वस्तुस्थिति पर नजर रख रहे विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री और हाईकमान का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश पर केंद्रित होने के कारण किसी भी प्रदेश के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा पा रही है। इसलिए हिमाचल को लेकर जो भी फैसला लिया जायेगा वह उत्तर प्रदेश की स्थिति के साथ ही जुड़ा होगा। इस समय दिल्ली, हरियाणा पंजाब, उत्तराखंड आदि प्रदेशों में भाजपा की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। हिमाचल में भी उप चुनाव के परिणामों में भाजपा के लिए खतरे के संकेत स्पष्ट दे दिये हैं। उधर आर.एस.एस. ने भी अपना पूरा ध्यान हिमाचल पर केंद्रित कर रखा है। प्रदेश की हर पंचायत में शाखा स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ के लिये हिमाचल कितना महत्वपूर्ण है और संघ का भाजपा में क्या स्थान है। प्रदेश में संघ और जयराम सरकार के रिश्तों को लेकर पिछले दिनों कई सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव के परिणामों के बाद संघ और हाईकमान दोनों ही कोई भी कड़ा फैसला लेने से कोई गुरेज नहीं करेगा। क्योंकि जहां हिमाचल आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है वहीं पर केंद्र द्वारा अब तक प्रदेश को करीब तीन लाख करोड़ दिये जाने के दावों का कोई खंडन तक जारी नहीं किया है। फिर इसी के साथ सीएजी की यह रिपोर्ट सामने आना की जयराम सरकार ने 96 योजनाओं पर एक भी पैसा तक खर्च नहीं किया है। इससे सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुये हैं। इस सब को एक साथ मिलाकर देखने से राज्य सरकार के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है।

राज्यपाल ने आईआईटी मंडी का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंडी जिला में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा किया।

इस अवसर पर संस्थान के फेकल्टी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमें समाज की आवश्यकता के अनुरूप तकनीक उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन एक गंभीर समस्या है और हिमाचल में इसके कारण हर वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए ऐसी तकनीक विकसित की जानी चाहिए जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान मिले।

उन्होंने इस दिशा में पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मंडी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि तकनीक को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग और राज्य के अन्य संबंधित विभागों को इस दिशा में आईआईटी मंडी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना चाहिए ताकि इस दिशा में सार्थक परिणाम हासिल किए जा सके।

स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के एमेरिटस प्रोफेसर एस.सी. जैन ने राज्यपाल को सम्मानित किया। उन्होंने संस्थान की उपलब्धियों और विभिन्न पहलो का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी अनुसंधान के अलावा समुदाय के साथ मिलकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह कर रहा है।

इससे पूर्व जिओ हजार्ड स्टडिंग ग्रुप की समन्वयक डॉ. कला वी. उदय ने भूस्खलन प्रबंधन पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी दिया। उन्होंने भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों की भी जानकारी दी।

इसके उपरान्त राज्यपाल ने संस्थान के परिसर में पौधा रोपण भी किया। राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, के.के. बजरे और फेकल्टी के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नववर्ष-2022 की शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि नव वर्ष प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आएगा। उन्होंने सभी लोगों से सामाजिक बुराइयां समाप्त करने और समाज के कमजोर वर्गो के कल्याण के लिए आगे आकर सहयोग देने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने शुभकामना संदेश में वर्ष 2022 में प्रदेश के लोगों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की है।

जय राम ठाकुर ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों के कड़े परिश्रम और समर्पण से प्रदेश विकास के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा और वर्ष 2022 में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा।

नए साल में भारतवर्ष फ़िर से विश्वगुरु बनने की ओर तेजी से हो अग्रसरः धूमल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने भारत की जनता को नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं दी हैं।

एक संदेश में उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नया साल भारत के लोगों और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और रोग मुक्त वातावरण लायेगा। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के शुभारंभ पर वह देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नववर्ष सबके लिए खुशहाली समृद्धि प्रसन्नता लेकर आये और कोरोना महामारी से सबकी हिफाज़त हो।

प्रो. धूमल ने लोगों से मास्क पहनकर और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के प्रकोप से बचाने के लिए उचित देखभाल करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में कोविड की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। 'इलाज से परहेज बेहतर है' इस स्वर्णिम नियम को याद रखें और अपने जीवन में भी अपनाएं। मास्क पहनें, दो मीटर की दूरी रखें, बार-बार हाथ धोते रहें।

नौणी विश्वविद्यालय और कौशल विकास निगम ने 8 कौशल विकास कार्यक्रम किए शुरू

शिमला/शैल। किसानों और युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए डॉ यशवंत सिंह परमार

औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के सहयोग से आठ कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए। दोनों संगठनों के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत यह कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विश्वविद्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आयोजित एक समारोह में सभी प्रशिक्षण समन्वयकों की उपस्थिति में नौणी विवि के कुलपति डॉ परविंदर कौशल द्वारा कौशल विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम समन्वयक डॉ. हरीश शर्मा ने मुख्य अतिथि और विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय स्टेशनों के सभी प्रशिक्षण समन्वयकों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास में मदद करेगा और प्रौद्योगिकी मॉडयूल के क्षेत्र-विशिष्ट हस्तांतरण से कृषक समुदाय में प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देगा।

डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर और इन कार्यक्रम की समन्वयक और प्रधान अन्वेषक डॉ. अंजू धीमान ने बताया कि विश्वविद्यालय ने कौशल विकास निगम के साथ समझौते के तहत कृषि और संबद्ध विज्ञान में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के तहत ज्ञान साझा करने और कौशल विकास और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए उद्योग-संबंधित सामग्री विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत 45 बेसिक स्तर और 16 मास्टर स्तर का प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे जिससे राज्य के 1220 किसानों को लाभ होगा।

सभा को संबोधित करते हुए डॉ. सनील ठाकुर, जीएम कौशल विकास निगम ने कार्यक्रम के शुभारंभ पर विश्वविद्यालय को बधाई दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि निगम विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रशिक्षुओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य उद्यमिता के साथ-साथ उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करना है।

इस अवसर डॉ परविंदर कौशल ने विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी करने और किसानों के कौशल को उन्नत करने की पहल के लिए निगम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिन आठ विषयों को चुना गया है, उनमें हिमाचल प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और किसान न केवल अपनी आजीविका कमा सकते हैं, बल्कि नौकरी प्रदाता भी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को विश्वविद्यालय की तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहिए और विभिन्न सरकारी योजनाओं की मदद से इन विषयों में अपना उद्यम शुरू करना चाहिए।

डॉ. कौशल ने बताया कि कुल 61 प्रशिक्षणों में से 27 मुख्य परिसर नौणी, आठ कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नेरी में और पांच कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, थुनाग में आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र और अनुसंधान केंद्र क्रमशः सात और 14 प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। डॉ. कौशल ने कहा कि विश्वविद्यालय मास्टर्स प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं का चयन करेगा ताकि उन्हें किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

कार्यक्रम सह समन्वयक डॉ. धर्मेश गुप्ता ने डॉ. कुमुद सिंह, एमडी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और उनकी टीम को विश्वविद्यालय को कृषि-बागवानी गतिविधियों में युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। निदेशक अनुसंधान डॉ. रविंदर शर्मा, निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ. दिवेंद्र गुप्ता, पुस्तकालय अध्यक्ष डॉ. एच.आर. शर्मा, छात्र कल्याण अधिकारी डॉ. जेके दुबे, वित्त नियंत्रक सी.आर. शर्मा और विभागाध्यक्ष सहित विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केन्द्रों के वैज्ञानिक और प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इन विषयों पर आयोजित होंगे सात दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम

खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, मशरूम की व्यावसायिक खेती(वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन(औषधीय और सुगंधित पौधों का उत्पादन और प्रसंस्करण(वाणिज्यिक फूलों की खेती और मूल्यवर्धन(टेम्परेट फल फसलों का कैनोपी प्रबंधन(टेम्परेट फल फसलों का प्रसार और नर्सरी प्रबंधन और सब ट्रॉपिकल फल फसलों का नर्सरी प्रबंधन।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

राज्यपाल से लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिला के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से राज

भवन में जिला लाहौल-स्पीति और किन्नौर के पंचायत प्रधानों, पिती बुद्धिस्ट लेखयुर सोगपा, स्पीति सिविल सोसायटी और पब्लिक वैल्फेयर सोसायटी के सदस्यों ने भेंट की। उन्होंने गरीब परिवारों को नौतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए जनजातीय जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों से छूट देने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया।

उन्होंने राज्यपाल से लगभग 11 किलोमीटर लम्बे लियो-चांगो बाईपास सड़क के कार्य में तेजी लाने और सुरक्षा के दृष्टिगत इसका निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से सीमा सड़क संगठन को स्थानांतरित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बाईपास सड़क के निर्माण से मलिंग नाला से सम्बन्धित सभी समस्याओं का समाधान होगा और 25 किलोमीटर की दूरी भी कम होगी।

राज्यपाल ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

पैरा-खेल राज्य चैपिंयनशिप में बेहतर प्रदर्शन पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने धर्मशाला में आयोजित छठी हिमाचल प्रदेश पैरा-खेल राज्य चैपिंयनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विशेष रूप से सक्षम सात खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 14 मेडल प्राप्त किए हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के अन्य विजेताओं और प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी सराहना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पैरा-खेल राज्य चौपिंयनशिप दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक बेहतर मंच है और इससे अन्य प्रतिभागियों को भी ऐसे ही आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए पांच पुल समर्पित करने पर रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया

शिमला/शैल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा देश के चार राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बी.आर. ओ.) द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर इस कार्यक्रम में शिमला से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है उनमें से पांच पुल हिमाचल प्रदेश में निर्मित किए गए हैं। मनाली-सरचू सड़क मार्ग पर बने कोठी-1 पुल, कोठी-2 पुल, कमांडर पुल और पातसियो पुल तथा पोवारी-पूह सड़क पर बने काशंग पुल देश की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग पर बने ये पुल जम्मू और कश्मीर तथा लेह में तैनात हमारे सैनिकों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पुलों का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। इनसे लाहौल स्पीति के केलांग सहित लेह-लद्दाख के वासियों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। अब यहां से न सिर्फ भारी सैन्य वाहन सुगमता से गुजर सकेंगे बल्कि स्थानीय जनता भी लाभान्वित होगी। यहां से सेब, आलू, मटर, बादाम और अन्य फसलें बाहर ले जाने में सुविधा होगी। ये पुल किन्नौर जिले की आर्थिकी को बढ़ाने में भी अहम योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बीआरओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीआरओ ने इस वर्ष आधारभूत ढांचे से जुड़ी 102 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों में लोगों का जीवन सरल बनाने और इन क्षेत्रों की आर्थिकी में सुधार करने में बी.आर. ओ. का अहम योगदान है।

इस अवसर पर प्रोजेक्ट दीपक, बी.आर.ओ, शिमला के कर्नल प्रणय डंगवाल और अधिशासी अभियंता पंकज कुमार शिमला में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने छोटा शिमला के मार्लब्रो हाउस में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति राज्य आयोग का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीम राव अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने न केवल भारत को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान दिया, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित किया।

जय राम ठाकुर ने आश्वासन दिया कि आयोग के सुचारू काम-काज के लिए सरकार कर्मचारी और पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्यों का भी शीघ्र ही मनोनयन कर लिया जाएगा ताकि आयोग सुचारू रूप से कार्य कर सके।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समान अधिकारों का विश्वास दिलाता है। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. वीरेंद्र कश्यप ने आयोग के नए कार्यालय के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उद्योग मंत्री ने जीएसटी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया

शिमला/शैल। वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की 46वीं बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने हिस्सा लिया।

बैठक में टेक्सटाइल पर जीएसटी की दर के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में सभी कपड़ा वस्तुओं के लिए 12 प्रतिशत की समान दर की सिफारिश की गई थी। कपड़ा क्षेत्र में इनवर्टेड डयूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया था और नई दरें 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होनी थीं।

बिक्रम सिंह ने राज्य का दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि कपड़ा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। कई बाधाओं के कारण कपड़ा क्षेत्र में नए निवेश नहीं हो रहे हैं। इस सेक्टर में निवेश को प्रभावित करने वाले कारणों में इनवर्टेड डयूटी स्ट्रक्चर एक महत्त्वपूर्ण कारक रहा है। उन्होंने कहा कि नए निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। उन्होंने कहा कि कर युक्तिकरण के मुद्दे को समग्र रूप से निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने परिषद से वर्ष-2027 तक जीएसटी मुआवजे को बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह किया।

जीएसटी परिषद ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 1 जनवरी, 2022 से दर परिवर्तन के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस क्षेत्र में कर दरों के युक्तिकरण के मुद्दे को दर युक्तिकरण के लिए गठित मंत्री समूह को संदर्भित करने का निर्णय लिया ताकि इस मुद्दे पर समग्र रूप से निर्णय लिया जा सके। मंत्रियों के समूह द्वारा फरवरी, 2022 में जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद की मार्च के पहले सप्ताह में बैठक होने की संभावना है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के दायरे में आएंगे 26,375 नए लाभार्थी:सरवीन चौधरी

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए 26375 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 1050 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को पूरा करते हुए 1 जनवरी, 2022 से 26,375 नए लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी।

सरवीन चौधरी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत बिलासपुर जिला के 372 लाभार्थी, चम्बा के 2,405, चम्बा जिला के पांगी और भरमौर से चार-चार, हमीरपुर से 1,639, कांगड़ा से 5,433, मण्डी से 3,527, कुल्लू से 2,241, शिमला से 3,143, सिरमौर से 3,279, सोलन से 1,589, ऊना से 2,491, किन्नौर से 170 और लाहौल-स्पीति जिला से 78 नए लाभार्थी शामिल किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि 26,375 नए आवेदनों को स्वीकृति के उपरान्त अब राज्य में वृद्धावस्था पेंशन के कुल लाभार्थियों की संख्या 6 लाख 35 हजार 375 हो गई है।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विरासत मामले समाधान योजना अधिसूचित की

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती (विरासत मामले समाधान) योजना, 2021 को मंजूरी प्रदान की है और यह अधिसूचित कर दी गई है। यह योजना विभिन्न फोरम में लंबित सभी विरासत मामलों के समाधान और बकाया राशि की वसूली करने में मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती (विरासत मामले समाधान) योजना-2021 एक महत्वकांक्षी योजना है और जीएसटी पूर्व करदाताओं के लिए कर देयता और विवादों को हल करने के लिए लाई गई है। इस योजना के तहत, करदाता बकाया कर राशि का भुगतान कर सकते हैं और कानून के तहत किसी भी अन्य परिणाम से मुक्त हो सकते हैं। इससे करदाताओं को संतोषजनक राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें ब्याज और जुर्माने के बदले केवल निपटान शुल्क देना होगा। करदाताओं को दस्तावेजों को संकलित करने, लंबित वैधानिक प्रपत्रों को एकत्र करने और आकलन को पूरा करने के लिए समाधान तैयार करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। जीएसटी लागू होने के उपरांत भी विभिन्न कंपनियों, उद्योग और डीलरों के पहले के विवाद लम्बित हैं।

यह योजना हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में योजना के प्रकाशन से छह महीने की अवधि के लिए वैध होगी। योजना के दो चरण होंगे। पहले चरण के चार महीनों में डीलर को 10 प्रतिशत की दर से निपटान शुल्क के साथ देय कर का भुगतान करना होगा और दूसरे चरण के दो महीनों में पहले चरण में लागू निपटान शुल्क का एक सौ पचास प्रतिशत कर (अर्थात 150 प्रतिशत) देय राशि के साथ अदा करना होगा। हितधारक या डीलर विभाग के संबंधित सर्कल या जिला कार्यालयों में जाकर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। डीलरों को लागू निपटान शुल्क संबंधित खाते के शीर्ष में ऑनलाइन जमा करना होगा और कोई मैन्युअल शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दिसम्बर माह में 342 करोड़ जीएसटी संग्रह

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जीएसटी के अन्तर्गत विभाग ने दिसम्बर माह में 342 करोड़ रुपये एकत्र किये। चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2021 तक जीएसटी संग्रह 3157.26 करोड़ रुपये रहा, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 2370.45 करोड़ रुपये था, जो गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि विभाग की कई पहलों में कर अधिकारियों की क्षमता निर्माण, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद गैर-फाइलर को नकारना, फील्ड अधिकारियों के प्रदर्शन की निगरानी, ई-वे बिलों का सत्यापन और इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल हैं, जिससे संग्रह में सुधार हुआ है।

प्रवक्ता ने कहा कि विभाग की योजना निकट भविष्य में टैक्स हाट कार्यक्रम आयोजित करने की है ताकि इसमें और सुधार किया जा सके।

वाणिज्यक वाहन सम्बन्धी समस्त कर परिवहन विभाग के अधीन लाए गए

शिमला/शैल। निदेशक परिवहन, अनुपम कश्यप ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्यक वाहन सम्बन्धी समस्त करों को परिवहन विभाग के अधीन कर दिया गया है और इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना 31 दिसम्बर, 2021 को जारी कर दी गई है। इससे अब ऑपरेटरों को वाहन सम्बन्धी कार्यों के लिए अलग-अलग विभागों में नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें परिवहन विभाग में ही ऑनलाईन सिंगल विन्डों सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से अब 1 जनवरी, 2022 से राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा लिए जा रहे यात्री एवं मालभार कर के स्थान पर विशेष पथ कर (एस.आर.टी) की अदायगी परिवहन विभाग को की जाएगी। इससे नये वाहन तुरन्त नई व्यवस्था में जुड़ जाएंगे जिसके लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन कर अदायगी प्रणाली विकसित की गई है, जिससे ऑपरेटर अपनी इच्छा एवं सुविधा अनुसार घर-द्वार, किसी अन्य स्थान से या लोक-मित्र केन्द्रों से विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाकर वाहन सम्बन्धी कर जमा करवा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों को इस व्यवस्था में जोड़ने से पूर्व राज्य कर एवं आबकारी विभाग में अदा किए गए कर का अनापत्ति प्रमाण पत्र करवाना होगा। ऐसे वाहन जिनका कर पूरे वर्ष का जमा है, वे भी अनापत्ति प्रमाण पत्र पर इस व्यवस्था से जुड़ सकते हैं।

उन्होंने समस्त ऑपरेटरों से अनुरोध किया कि वे शीघ्र ही विभाग की नई व्यवस्था से जुड़ें एवं इसका लाभ उठाएं। ऑपरेटर कर सम्बन्धी समस्याओं के निवारण के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या दूरभाष नम्बर 0177-2803138 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या कोरोना का राजनीतिक उपयोग हो रहा है?

क्या कोरोना के नये वायरस ओमीक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कुछ समय के लिये टाल दिये जायेंगे। यह सवाल इलहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद चर्चा में आया हैं क्योंकि इस आदेश में चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से निर्देश पूर्ण आग्रह किया गया है। इस पर क्या फैसला लिया जाता है यह आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जायेगा। लेकिन जिस तरह से ओमीक्रॉन के बढ़ने और उसी अनुपात में सरकारों द्वारा कर्फ्यू आदि के कदम उठाये जा रहे हैं इससे एक बार फिर लॉकडाउन की संभावनाएं और आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 2 वर्ष से देश इस महामारी के संकट से जूझ रहा है। इस दौरान जो कुछ घटा है और सरकार ने जो कदम उठाये हैं उसके परिदृश्य में कुछ सवाल उभरते हैं जिन पर एक सार्वजनिक बहस की अब आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाकर इस महामारी से निपटने का पहला कदम उठाया था। लॉकडाउन की घोषणा अचानक हुई थी। लोगों की लॉकडाउन झलेने की कोई तैयारी नहीं थी। जबकि महामारी अधिनियम 1897 में यह प्रावधान है कि जब कोई बीमारी सरकार के आकलन में महामारी लगे और उससे निपटने के लिये अलग से कुछ कदम उठाने पड़े तो उसके लिए जनता को सार्वजनिक रूप से अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। लेकिन लॉकडाउन लगाते समय कुछ नहीं किया गया। लॉकडाउन में किस तरह का नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ा है उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। नवम्बर 2016 में की गयी नोटबंदी से जो नुकसान आर्थिकी को पहुंचा था लॉकडाउन ने उसे कई गुना बढ़ा दिया है। इस दौरान राजनीतिक गतिविधियों के अतिरिक्त बाकी सारी आर्थिक गतिविधियां शुन्य हो गयी। 2020 में कोरोना के लिये कोई वैक्सीन या अन्य कोई दवाई बाजार में नहीं आयी। आज भी इसकी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष जनवरी से जो वैक्सीन लगाई जा रही है वह केवल एक प्रतिरोधक उपाय है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी केवल छ: माह तक कारगर है। इसके बाद पुन: इसकी डोज लेनी पड़ेगी। ऐसा कब तक करते रहना पड़ेगा इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वैक्सीन की इस व्यवहारिक स्थिति के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने एक शपथ पत्र देकर यह कहा है की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं किया गया है। इसे ऐच्छिक ही रखा गया है। 2020 में आरोग्य सेतु ऐप आया था। इसको लेकर कितने दावे किये गये थे और उन्हीं दावों के आधार पर इसे अनिवार्य बना दिया गया था। लेकिन जब एक आर.टी.आई. में इससे जुड़ी जानकारियां मांगी गयी तब ऐप को लेकर ही अनभिज्ञता जता दी गयी। इससे आम आदमी के विश्वास को कितना आघात पहुंचा है इसका अंदाजा लगाना कठिन है।

1897 में महामारी अधिनियम आने के बाद से लेकर आज तक का रिकार्ड यह बताया है कि हर दस-बारह वर्ष के अंतराल पर कोई न कोई महामारी आती रही है लेकिन इससे निपटने के इस तरह के उपाय पहली बार किये गये हैं जिनमें शुरुआत में ही यह कहा गया कि अस्पताल भी ना जायें। इस निर्देश में यह ध्यान नहीं रखा गया कि जो लोग ओ.पी.डी. में आ रहे हैं या अस्पताल में दाखिल होकर इलाज करवा रहे हैं और अब उनका इलाज बंद हो गया है उनमें से यदि कोई संक्रमित हो जाता है तो उसका बचाव कैसे होगा। आज तक इस पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है कि जब 24 मार्च को लॉकडाउन के कारण अस्पताल भी बंद हो गये थे तब अस्पताल आने वाले कितने लोग संक्रमित हुए और उनकी स्थिति क्या रही। जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डॉ कुनाल साहा की आई थी उसमें संभावित प्रस्तावित दवाइयों और वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कुछ चिन्ताएं व्यक्त की गयी थी। जिनका आज तक जवाब नहीं आया है। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों और फिर कुछ पूर्व वरिष्ठ नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कुछ जानकारीयां इस महामारी को लेकर मांगी थी जिनका जवाब नहीं आया है। अब डॉक्टर जैकब पुलियेल की याचिका पर यह शपथ पत्र आ गया कि वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं की गयी है यह ऐच्छिक है। लेकिन व्यवहार में जिस तरह की बंदिशों के आदेश/निर्देश सामने आ रहे हैं वह रिकॉर्ड पर आ चुकी स्थिति से एकदम भिन्न है। इस भिन्नता के कारण ही यह आशंकाएं उभर रही हैं कि कहीं इस महामारी का कोई राजनीतिक लाभ तो नहीं उठाया जा रहा है। क्योंकि जन्म और मृत्यु के आंकड़े संसद में गृह विभाग की ओर से हर वर्ष रखे जाते हैं। क्योंकि हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है। मृत्यु के इन आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षो से इसमें प्रतिवर्ष दस बारह लाख की बढ़ोतरी हो रही है। 2018 में यह आंकड़ा 69 लाख था और आज भी यह 7.27 प्रति हजार है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवहार और प्रचार में कितना अंतर है।

हिमाचल प्रदेश बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआंमुक्त राज्य

राज्य सरकार ने घर-घर नि:शुल्क उपलब्ध करवाए गैस कनेक्शन, गृहिणियों की रसोई हुई उज्ज्वल

शिमला। केंद्र की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत दिसम्बर 2019 में हिमाचल देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है।

धुएं से होने वाली बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने भी योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की।

केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 21.81 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल में 1.36 लाख नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए, जबकि हिमाचल सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत करीब 120 करोड़ रुपये खर्च कर 3.23 लाख गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए।

मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत 26 मई, 2018 को हुई। केंद्र और प्रदेश सरकार के कारण आज प्रदेश की महिलाओं को खाना बनाते समय चूल्हे के धुएं से छुटकारा मिला है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यान्वित की जा रही इस योजना के तहत गैस कनेक्शन रहित परिवारों को एलपीजी कनेक्शन नि:शुल्क वितरित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना को शुरू करने का उद्देश्य उन परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करना था, जो केंद्र की उज्ज्वला योजना के दायरे में नहीं आये थे। उज्ज्वला योजना के तर्ज पर ही प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। केंद्र सरकार की ओर से चलायी जा रही उज्ज्वला योजना और प्रदेश की सरकार की मुख्यमंत्री गृहिणी योजना हिमाचल की महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के फलस्वरूप ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता कम हुई है। साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य पर धुंए से पड़ने वाले विपरित प्रभाव से भी मुक्ति मिली है। इन योजनाओं की वजह से महिलाओं का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है।

ट्राइफेड ने आदिवासी विकास को लेकर अनुसंधान परियोजनाएं चलाने के लिए पहल की

ट्राइफेड आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए कई कार्यक्रम और पहल चला रहा है। हाल के दिनों में ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित वन धन कार्यक्रम इस दिशा में एक प्रमुख पहल है, जो लघु वनोपज (एमएफपी) की उपलब्धता के साथ-साथ महत्वपूर्ण वनवासी आदिवासी जनसंख्या वाले 25 राज्यों और 307 जिलों में संचालित है।

ट्राइफेड ने अपनी गतिविधियों का विस्तार करने और अधिक आदिवासियों की मदद करने के लिए 29 दिसंबर, 2021 को रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी-नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर (आरएमपी-एनएफपीआरसी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि ज्ञान, विशेषज्ञता और संस्थागत ताकत का लाभ उठाने में सहयोगात्मक प्रयास किया जा सके। संयुक्त उद्यम में निम्नलिखित रणनीतिक क्षेत्र शामिल होंगे:

* आदिवासी विकास और संबंधित गतिविधियों को लेकर विकास कार्यों और अनुसंधान परियोजनाओं का निष्पादन।
* वन धन योजना जैसी मौजूदा और आने वाली सरकारी योजनाओं का आकलन और समीक्षा।
* संयुक्त रिपोर्ट, या किसी अन्य प्रकाशन (प्रकाशनों) के रूप में अनुसंधान के निष्कर्ष का प्रकाशन।
* अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रसारित करना, सत्र आयोजित करना और विषय के विशेषज्ञों के साथ बैठकें करना।
* सम्मेलनों, संगोष्ठियों और अनुसंधान से संबंधित ऐसी अन्य गतिविधियों की संयुक्त रूप से मेजबानी करना।
* सूचना का आदान-प्रदान, अनुसंधान के लिए संबंधित कार्मिकों और डेटा तक पहुंच प्रदान करना।
* पारस्परिक तौर पर वांछनीय पाए जाने पर इस समझौते के बाहर अन्य समान विचारधारा वाली संस्थाओं के साथ सहयोग करना।
* परियोजना से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी जानकारी हेतु पहुंच प्रदान करना।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन की प्रणाली तथा लघु वनोपज के लिए मूल्य श्रृंखला विकास योजना आदिवासी इको-सिस्टम को इस तरह प्रभावित किया है, जो अभूतपूर्व है। ट्राइफेड द्वारा देश के 21 राज्यों में राज्य सरकार की एजेंसियों के सहयोग से लागू की गई इस योजना के माध्यम से अप्रैल 2020 से सीधे तौर पर जनजातीय अर्थव्यवस्था में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया गया है। मई 2020 में सरकार की सहायता से लघु वनोपज की कीमतों (एमएफपी) में 90 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई और एमएफपी सूची में 23 नई वस्तुओं को शामिल किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय की यह एक प्रमुख योजना है, जो 2005 के वन अधिकार अधिनियम से सशक्त होती है। इसका उद्देश्य वनोपज के आदिवासी संग्रह कर्ताओं के लिए समुचित पारिश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करना है।

वन धन विकास योजना, एमएसपी को कुशलता से पूरा करती है और आदिवासी संग्रहकर्ताओं तथा वनवासियों एवं घर में रहने वाले आदिवासी कारीगरों के लिए रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में उभरी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन मूल्य वलधत उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय सीधे आदिवासियों को मिले।

ट्राइफेड जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में अपने मिशन को जारी रखने के लिए संगठनों, सरकारी तथा गैर-सरकारी एवं शैक्षिक संस्थाओं से जुड़ने के लिए प्रयासरत है। ट्राइफेड वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और वन धन योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से आदिवासी लोगों के लिए आय और आजीविका पैदा करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है।

उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए एनईपी-2020 के तहत पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020

प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 शुरू की गई थी। उसके बाद के वर्ष में उच्च शिक्षा विभाग (डीओएचई) की ओर से कई तरह की पहल की गई हैं।

i) उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए (ए) यूजीसी (विश्वविद्यालय के लिए संस्थान) विनियमन 2019 में संशोधन किया गया और (बी) उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप से अंतर्निहित डिग्री प्रोग्राम प्रदान कर सकें, इसको लेकर यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

ii) 3054 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षुता) के माध्यम से लगभग 9 लाख छात्रों को रोजगार योग्य बनाएगा। इस योजना के तहत छात्रों को उभरती और आगे की तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, नए विकसित और उभरते क्षेत्रों में उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और सरकार के पीएम गति शक्ति कार्यक्रम में प्रशिक्षुता दी जाएगी।

iii) अप्रेंटिसशिप स्कीम और इंटर्नशिप एंबेडेड कोर्स एक स्थायी कुशलता का इको सिस्टम तैयार करेगा। इंजीनियलरग शाखा के अलावा मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान के छात्रें को अप्रेंटिस देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का दायरा बढ़ाया गया है।

iv) छात्रों को इंटर्नशिप का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए एआईसीटीई की ओर से इंटर्नशिप पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल पर वर्तमान में 12.35 लाख प्रशिक्षुता, 73 लाख छात्र और 38650 नियोक्ता पंजीकृत हैं।

v) बड़े बहु विषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर, मास्टर और डॉक्टरेट शिक्षा में कठिन अनुसंधान आधारित विशेषज्ञता देने से शिक्षा, सरकार और उद्योग सहित बहु विषयक कार्यों में अवसर मिलेगा। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा 29.07.2021 को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया गया। यह अकादमिक बैंक विभिन्न मान्यता प्राप्त एचईआई से प्राप्त अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा ताकि किसी उच्च शिक्षा संस्थान से अर्जित किए गए क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए डिग्रियां प्रदान की जा सकें। यूजीसी ने विनियमों के माध्यम से एचआई को आवश्यक सक्षम तंत्र उपलब्ध कराया है।

vi) . एक से ज्यादा बार प्रवेश और निकास बिंदुओं को सक्षम बनाने के लिए वर्तमान की कठिन सीमाओं को हटाने और जीवन भर सीखने के लिए नई संभावनाएं पैदा करने को लेकर यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश/निकास पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

vii) सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिक्षण और सीखना विकल्पों में से एक है। इसके अनुसार यूजीसी ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम 2020 को अधिसूचित किया और यूजीसी (स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन पाठयक्रम के लिए क्रेडिट फेमवर्क) विनियमन 2021, जिसमें ऑनलाइन पाठयक्रमों की पेशकश करने के लिए एचईआई की योग्यता को व्यापक आधार दिया गया है साथ ही एमओओसी स्वयं का उपयोग करके क्रेडिट के लिए अनुमत पाठयक्रमों के प्रतिशत को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

viii) इंस्टीटयूट ऑफ एमिनेंस आईओई को ऑफशोर कोर्स (शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए) की पेशकश करने के लिए यूजीसी ने यूजीसी (प्रतिष्ठित डीम्ड संस्थान विश्वविद्यालय बन सकते हैं) अधिनियम में संशोधन किया गया है।

ix) भारतीय ज्ञान व्यवस्था, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) में नॉलेज सेल (ज्ञान प्रकोष्ठ) की स्थापना की गई है।

x) .शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लक्ष्य को प्राप्त करने, और/या द्विभाषी कार्यक्रमों की पेशकश करने, सकल नामांकन अनुपात की पहुंच और ताकत बढ़ाने और सभी भारतीय भाषाओं के गुण के उपयोग और जीवंतता को बढ़ावा देने के लिए जेईई (मेन) और एनईईटी (यूजी), इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय परीक्षाएं अंग्रेजी के अलावा 12 भाषाओं में आयोजित की गई हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने शैक्षणिक वर्ष 2021–22 से दस राज्यों में छह भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठयक्रम चलाने के लिए 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों को मंजूरी दी है।

xi) एआईसीटीई ने (एआईसीटीई ट्रांसलेशन ऑटोमेशन एआई टूल नामक उपकरण भी विकसित किया है, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी भाषा के ऑनलाइन पाठयक्रमों को ग्यारह विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंच बनाई जा सके।

स्वयं

i) स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक पेश पाठयक्रमों के लिए क्रेडिट ट्रांसफर को स्वीकार करने को लेकर एक सौ चौवन (154) विश्वविद्यालय पटल (बोर्ड) पर आ गए हैं।

ii) शैक्षणिक वर्ष 2022–23 से कला, वाणिज्य और विज्ञान और इंजीनियरिंग में प्रथम वर्ष के पाठयक्रमों को अंग्रेजी के अलावा 12 स्थानीय भाषाओं में स्वयं मंच पर उपलब्ध कराने की योजना है ताकि स्थानीय माध्यम से छात्रें को अच्छी तरह से अध्ययन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एएल और एमएल का उपयोग किया जाएगा।

ई – पीजीपाठशाला: पीजी पाठयक्रमों का ऑनलाइन प्रवेशद्वार

i) सूचना संचार प्रौद्योगिकी (एनएमई–आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को किसी भी समय किसी भी समय उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने को लेकर केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है ।

ii) यह भारत में पीजी पाठयक्रमों की सामग्री वाले सबसे बड़े ओईआर संग्रह में से एक है।

iii) यह शिक्षकों और छात्रें की बेहतरी को लेकर पीजी कार्यक्रमों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई–सामग्री प्रदान करता है।

iv) यह विभिन्न प्रकार की असमानताओं जैसे अमीर/गरीब, शहरी/ग्रामीण, जाति और धर्म आधारित असमानताओं, भौगोलिक विषमताओं, क्षेत्रीय असमानताओं आदि का भी समाधान करता है।

v) 67 विषयों में 23000 से ज्यादा ई–मॉडयूल वाले 778 पेपर तैयार किए गए हैं, इनमें 23 विषयों में पूरे पाठयक्रम/सिलेबस को शामिल किया गया है।

vi) अंतरराष्ट्रीय समेत लगभग 1.3 करोड़ से अधिक लोगों ने ई–पीजी पाठशाला साइट का मुआयना किया है। अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों का विवरण इस प्रकार है: यूएसए से 11843, यूके से 7190, ऑस्ट्रेलिया से 8615, रूस से 13579, पाकिस्तान से 7215, यूएई से 3924, चीन से 28745, न्यूजीलैंड से 366, जापान से 6722 और जर्मनी से 23592 लोगों ने साइट का विजिट किया है।

vii) यू–टयूब चैनल विद्या–मित्र के 557000 सब्सक्राइबर (अभिदाता) हैं और कुल 63864531 वीडियो देखे जा चुके हैं।

viii) विश्वविद्यालयों द्वारा मिश्रित (ब्लेंडेड) शिक्षा के लिए ई–पीजीपाठशाला सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

ix) पीजी पाठशाला की सामग्री को आई–एलएमएस के माध्यम से कई विश्वविद्यालयों को सीखने की प्रबंधन प्रणाली के लिए वितरित किया गया है।

x) दो उप उत्पाद जैसे ई–पाठय (सभी ई–पीजी वीडियो के लिए ऑफलाइन एक्सेस) और ई–अध्यायन (ई–बुक्स) विकसित किया गया है।

xi) हाल ही में कोविड 19 लॉकडाउन के कारण सभी विश्वविद्यालयों में ई–पीजीपाठशाला वेबसाइट का व्यापक रूप से उपयोग किया गया और कई विश्वविद्यालयों ने ई–पीजीपाठशाला सामग्री को रूम में एक नजर देखने के रूप में उपयोग किया है।

xii) यूजीसी ने 2020 में ई–पीजी पाठशाला परियोजना की समीक्षा के लिए एक मूल्यांकन /परिणाम समीक्षा समिति का गठन किया।

समिति ने महसूस किया कि ई–पीजीपाठशाला शिक्षकों के साथ–साथ छात्रों के लिए मुक्त शिक्षा संसाधन के रूप में बहुत उपयोगी साबित हुई है और इस योजना को जारी रखने की जोरदार अनुशंसा की और सिफारिश की कि ई–पीजी पर अपलोड किए गए पाठयक्रमों का अनुवाद करने के प्रयास किए जाने चाहिए। पाठशाला पोर्टल शुरू में आठ क्षेत्रीय भाषाओं हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला और गुजराती में इसे करेगा।

आजादी का अमृत महोत्सव

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 75 गुमनाम नायकों, घटनाओं, स्थानों, संगठनों और साहित्य की पहचान करने के लिए देशव्यापी संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है, जिसका बाद में प्रकाशन किया जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अज्ञात और गुमनाम नायकों/ व्यक्तियों, विस्मृत स्थानों और घटनाओं को लेकर 75 पुस्तकों का प्रकाशन कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उन गुमनाम व्यक्तियों पर 75 पुस्तकें भी प्रकाशित कर रहा है जिन्होंने आजादी के बाद देश को संवारने में अपना योगदान दिया है। जनवरी 2022 को नवाचार इको सिस्टम मनाने के लिए चिन्हित किया गया है।

इस महीने के दौरान मंत्रालय का नवाचार प्रकोष्ठ छात्र नवाचारों को प्रदर्शित करने, छात्रों और संकाय द्वारा विकसित 75 अभिनव तकनीकों को धन देने और इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने साथ ही बौद्धिक संपदा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए (कपिला अभियान) शुरू करने को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा।

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतर स्नातक व स्नातक प्रवेश और फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एनटीए प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त परीक्षण संगठन के रूप में कार्य करेगा। इसके तहत यह निर्णय लिया गया है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022–23 से प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) में एक समान प्रवेश परीक्षा होगी।

यह परीक्षा वैचारिक समझ और ज्ञान को लागू करने की क्षमता का परीक्षण करेगी। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने की आवश्यकता को समाप्त करना होगा। इस प्रक्रिया से छात्रों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों एवं पूरी शिक्षा व्यवस्था पर बोझ कम होगा।

राज्य पात्रता परीक्षा एसईटी

वर्ष 2021 के दौरान यूजीसी ने एसईटी आयोजित करने को लेकर निम्नलिखित राज्य नोडल एसईटी एजेंसियों को मान्यता दी :

तमिलनाडु एसईटी (नोडल एजेंसी. अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु)

पश्चिम बंगाल एसईटी (नोडल एजेंसी. पश्चिम बंगाल कॉलेज सेवा आयोग)

जम्मू कश्मीर और लद्दाख एसईटी (नोडल एजेंसी. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू)

एक भारत श्रेष्ठ भारत

एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मंत्रलय ने दो मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। इनमें पहले भाषा संगम में 22 भारतीय भाषाओं में दैनिक बातचीत के 100 वाक्यों का संग्रह है और इसका उद्देश्य एकेएम अवधि के दौरान कम से कम 75 लाख लोगों को सिखाना है। दूसरा मोबाइल ऐप भारत के विभिन्न राज्यों पर मजेदार क्विज गेम (खेल प्रश्नोत्तरी) है। दोनों ऐप्स में स्वयं परीक्षण और प्रमाण पत्र उत्पत्ति की गुंजाइश हैं।

उन्नत भारत अभियान

i) ग्रामीण जिलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्नत भारत अभियान योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को समझने और काम करने के लिए प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों (केंद्रीय और राज्य, सार्वजनिक और निजी) को शामिल करना है।

ii) ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाने के इरादे से उच्च शिक्षा संस्थानों से कम से कम 5 गांवों को गोद लेने और स्थानीय जरूरतों के अनुसार उपलब्ध तकनीकों को अनुकूलित करने और मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कार्यक्रम तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से ग्रामीण भारत के संवर्धन पर केंद्रित है। अभी तक 2897 (–2900) संस्थाएं भाग ले रही हैं और योजना के तहत –14500 गांवों को उनके द्वारा गोद लिया गया है। इस योजना को 48.53 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय पर और 5 साल की अवधि के लिए मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

छात्रवृत्ति योजनाएं

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना

i) 06.07.2021 को आयोजित अपनी बैठक में ईएफसी ने कुल 1325.00 करोड़ रुपये की लागत से सीएस योजना (कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति) को जारी रखने की सिफारिश की।

ii) शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के लिए 18 अगस्त 2021 को नए और नवीनीकरण (फेश और रिन्यूअल) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को खोला गया है। अब तक एनएसपी पर 99957 नए और 115582 नवीनीकरण आवेदन प्राप्त हुए हैं।

iii) इस वर्ष (नवंबर तक) 166.78 करोड़ रुपये से 157528 छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं।

केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना सीएसआईएस और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल)

i) 06.07.2021 को आयोजित अपनी बैठक में ईएफसी ने 7721.19 करोड़ रुपये की लागत से सीएसआईएस और सीजीएफएसईएल को अगले पांच वर्षों के लिए 2021–22 से 2025–26 तक जारी रखने की सिफारिश की।

ii) पीएफएमएस के साथ सफलतापूर्वक केनरा बैंक वेब पोर्टल का पीएफएमएस एकीकरण किया गया। नए पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से भुगतान फाइलें स्थानांतरित की जा रही हैं।

iii) सीएसआईएस योजना के तहत दावा वर्ष 2020–21 के लिए वेब पोर्टल 01.11.2021 को 31.12.2021 तक खोला गया।

iv) आर/ओ की संख्या 794694 के दावों को लेकर सीएसआईएस और सीजीएफएसईएल के तहत कुल 1623.52 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

जम्मू कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना

i) ईएफसी ने 06.07.2021 को हुई बैठक में वित्त वर्ष 2021–22 से 2025–26 के दौरान जम्मू.कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना को 1111.81 करोड़ रुपये की कुल लागत से जारी रखने की सिफारिश की थी।

ii) इस वर्ष (नवंबर तक) कुल 144 करोड़ रुपये से 14665 छात्रवृत्ति वितरित की गई है।

सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय

लद्दाख के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मानसून सत्र में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और इसे 13.08.2021 को अधिसूचित किया गया।

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी

i) एचईएफए स्वास्थ्य मंत्रालय के एचईआई, केवी, एनवी, एम्स और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्त प्रदान करता है।

ii) 2022 तक की परियोजनाओं को निधि देने के लिए 100000 करोड़ रुपये है।

iii) 30 नवंबर 2021 तक 43115.00 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

iv) 32807.06 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई और वस्तुत: 12892.98 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

v) एचईएफए के माध्यम से वित्त पोषण करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की संख्या 97 है।

आईआईएसईआर

आईआइएसईआर तिरुपति और आईआईएसईआर बेरहामपुर के स्थायी परिसरों को क्रमश: 1137.16 करोड़ और 1129.32 करोड़ रुपये की पूंजी लागत के साथ स्थापित किया जाएगा। आईआईएसईआर तिरुपति और बरहमपुर ने अगले साल से स्थायी परिसरों में शिफ्ट करने की योजना बनाई है।

विश्वविद्यालय बनने वाले डीम्ड संस्थान

i) वर्ष 2021 के दौरान मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001 को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। ग्यारह प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

ii) यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12 बी के तहत निम्नलिखित डीम्ड विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है:

1.श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, पुडुचेरी।

2.वेल्स इंस्टीटयूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज (वीआईएसटीएएस), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु।

3.भारत उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु

iii) निम्नलिखित डीम्ड विश्वविद्यालयों के ऑफ.कैंपस केंद्र को मंजूरी दी गई है।

1.एस. आर. एम. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु।

2.आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन हैदराबाद, तेलंगाना।

महिला अध्ययन/जेंडर सेंसिटाइजेशन (लिंग संवेदीकरण) अनुभाग

i) इस योजना के तहत वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 159 महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

ii) यूजीसी ने महिला अध्ययन केंद्रों के लिए विशिष्ट/स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

iii) यूजीसी ने 07.12.2021 को विश्वविद्यालयों /संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यस्थल (महिला कर्मचारियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण विनियम 2015) में यौन उत्पीड़न पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रमों के लिए परामर्श जारी किया है।

iv) **यौन उत्पीड़न के मामलों पर वार्षिक विवरण**:यूजीसी साल में एक बार सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को परामर्श भेजकर यौन उत्पीड़न के मामलों पर वार्षिक विवरणी के संबंध में जानकारी भेजने और आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने व सक्षम वेबपोर्टल पर लिंग लेखा परीक्षण का ऑनलाइन विवरण भरने के अनुरोध के साथ अपने संबद्ध कॉलेजों को भी सूचित करने का आग्रह किया है। नवीनतम एडवाइजरी 10.06.2021 को अपलोड की गई है।

v) लिंग चैंपियंस के दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए रू यूजीसी साल में एक बार सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जेंडर चैंपियंस के दिशानिर्देशों को लागू करने के अनुरोध के साथ एडवाइजरी भेजता है और सक्षम वेब पोर्टल पर जेंडर चैंपियन के ऑनलाइन विवरण भरने के साथ अपने संबद्ध कॉलेजों को भी इसकी सूचना देने का आग्रह किया है। नवीनतम एडवाइजरी 13.07.2021 को अपलोड की गई है। सभी एडवाइजरी यूजीसी की वेबसाइट: www.ugc.ac.inऔर saksham.ugc.ac.in. पर उपलब्ध हैं।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

i) 2021 में स्टाइपेंडियम हंगारिकम कार्यक्रम के तहत 173 भारतीय छात्रों को सम्मानित किया गया।

ii) भारत–इजरायल संयुक्त अनुसंधान योजना के तहत कार्यक्रम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कर रिपोर्ट तैयार की गई।

iii) 2021 में एनईपी के अनुरूप उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर 29.07.2021 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे, विश्वविद्यालयों में 164 अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय स्थापित किए गए जबकि 156 विश्वविद्यालयों ने एलुमनी कनेक्ट सेल की स्थापना की।

मुख्यमंत्री ने किया मनाली में विंटर कार्निवल का शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मनाली के प्रसिद्व हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना करके, परिधि गृह मनाली से कार्निवल परेड को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रू स्तरीय पांच दिवसीय विंटर कार्निवल का शुभारम्भ किया। इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने लगभग 41 करोड़ रुपये से अधिक लागत की

विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए और राज्य स्तरीय स्वर्णिम वन महोत्सव का उदघाटन किया।

मुख्यमंत्री ने 16.93 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रामशीला उच्च मार्ग से भेखली-जिन्दौड़-ब्यासर सड़क, 3.97 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मढ़ी-गधेरनी-शलीण सड़क, 1.78 करोड़ रुपये की लागत से हरीपुर नाला पर निर्मित पुल, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्व खेल संस्थान मनाली के आर्टिफिशियल रॉक क्लाईबिग वॉल तथा 50 लाख रुपये की लागत से बने वन परिक्षेत्र कार्यालय मनाली का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नेचर पार्क ब्यास-बिहाल तथा 26 लाख रुपये की लागत से निर्मित स्वर्णिम वाटिका कोठी का लोकार्पण तथा 30 लाख रुपये की लागत से बनने वाले हामटा-छिक्का वन निरीक्षण मार्ग का शिलान्यास, 89 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले खनौरा नाला पर जीप योग्य पुल तथा 12 करोड़ रुपये से बाहंग में ब्यास नदी पर बस योग्य पुल का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्रै जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर मनु रंगशाला में दीप प्रज्ज्वलित करके शरद उत्सव में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया।

जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि घाटी में नए पुलों व सड़कों के निर्मित हो जाने से विभिन्न स्थान पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित होंगे, जिससे क्षेत्र में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि रॉक क्लाईविंग वाल के निर्मित होने से साहसिक खेलों में रूचि रखने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलने से मनाली में साहसिक पर्यटन गतिविधियां सुदृढ़ होगी। ब्यास बिहाल नेचर पार्क बनने से पर्यटकों को स्वच्छ व सुन्दर प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध होने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि वनों के महत्व के दृष्टिगत प्रदेश सरकार वन क्षेत्र के विस्तार और सदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दे रही है। गत चार वर्षो में प्रदेश में वन महोत्सव के दौरान 4 करोड़ 38 लाख 12 हजार पौधों का रोपण किया गया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर महिला मंडलों, विभिन्न विभागों, संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई झांकियों का अवलोकन भी किया। झांकियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, प्राचीन विरासत, मान्यताओं, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कोविड संक्रमण से बचाव, टीकाकरण, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक खेती आदि विषयों का संदेश दिया गया।

महंगाई, बेरोजगारी व प्रदेश जनहित के मुद्दे संसद में उठाएगी:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। सासंद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश में चारों उप चुनावों में पार्टी की शानदार जीत के लिये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूरी कांग्रेस टीम को

बधाई देते हुए कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भी अपनी जीत का परचम लहेरयागी। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय सीट पार्टी के लिये एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि इस चुनौती को पार करने में कांग्रेस सफल रही। इस जीत का एक बड़ा संदेश प्रदेश में ही नही, पूरे देश मे गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश व उत्साह पैदा हुआ है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की स्मृति में कांग्रेस का वार्षिक कलेंडर के विमोचन के अवसर पर प्रेस को सम्बोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने इस आयोजन के लिये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आभार प्रकट किया।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह एक ऐसे नेता थे जो लोगों के दिलों पर राज करते थे। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान उन्होंने देखा कि लोगों ने अपने घरों में उनकी याद में उनकी फोटो व स्मृतियों को संजो कर रखा है। उन्होंने कहा कि आज भले ही वीरभद्र सिंह उनके बीच नही है पर उनके कार्य, उनका प्यार, आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा और उनका मार्गदर्शन करेगा।

प्रतिभा सिंह ने मंडी में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के सवाल पर कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री प्रदेश के विकास को कोई राहत पैकेज देंगे, पर ऐसा कुछ नही हुआ। मोदी ने मंडी व कुल्लू की भाषा बोल कर लोगों को खुश करने का असफल प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उप चुनावों में महंगाई व बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे थे और लोगों ने इसके विरोध में कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने कहा कि वह ससंद में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व प्रदेश के जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए बड़े हवाईअडडों के निर्माण व उनके विस्तार की बहुत आवश्यकता है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता, पदाधिकारी सेवा दल के सदस्य सहित कई अन्य कार्यकता मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 10620 करोड़ रुपये की विभिन्न बाह्य परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पिछले चार वर्षो के दौरान हिमाचल प्रदेश को 10620 करोड़ रुपये की विभिन्न बाह्य परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

विज्ञान भवन नई दिल्ली में वर्ष 2022-23 के केन्द्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक को सम्बोधित करते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्रालय राज्य को निरंतर उदार वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य में आधारभूत संरचना के विकास के 400 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाए।

सेब पर आयात शुल्क का मुद्दा उठाते हुए जय राम ठाकुर ने इसे 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने पर बल दिया ताकि हिमाचली सेब और इसके माध्यम से जीविकोपार्जन कर रहे अढ़ाई लाख परिवारों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि सेब प्रदेश की मुख्य बागवानी फसल है और यह राज्य की एक बड़ी आबादी के जीविकोपार्जन का प्राथमिक स्त्रोत है। लेकिन राष्ट्रीय बाजार में आयातित सेब भारी मात्रा में पहुंचने से हिमाचल के सेब के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है जिससे राज्य के बागवानों को राजस्व का घाटा हो रहा है। ऐसे में आयात शुल्क में बढ़ोतरी करने के साथ ही सेब को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) की फल एवं अन्य माल सूची से बाहर रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंडी जिला में चिन्हित भूमि को ग्रीन फील्ड हवाई अडडे के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया है और इसके लिए अन्तिम तकनीकी सहमति भी प्रदान कर दी है। ऐसे में उन्होंने इस परियोजना को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रस्तावित हवाई अडडे को राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना घोषित करने का आग्रह करते हुए कहा कि लेह से समीप होने के कारण इस हवाई अडडे का सामरिक महत्त्व है। इस हवाई अडडे के निर्माण की अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेल और हवाई सम्पर्क के साधन बहुत ही सीमित हैं और वर्तमान में शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में हवाई पटी छोटी होने से वे केवल छोटे जहाजों के संचालन के लिए ही उपयुक्त हैं। इन परिस्थितियों में मंडी हवाई अडडे का निर्माण हिमाचल प्रदेश के लिए समय की मांग है।

जय राम ठाकुर ने वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा की सुविधा अगले तीन वर्ष तक जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहां कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियां देश के शेष भागों से अलग हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय सहायता के रूप में वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा और राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त करता है और इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा केवल जून, 2022 तक ही प्रभावी है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के राजस्व घाटा अनुदान में भी आगामी वर्षो में कमी प्रस्तावित है जिससे राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने वस्तु एवं सेवाकर मुआवजा सुविधा जारी रखने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास योजना-2017 को अगले पांच वर्षो के लिए जारी रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश सम्मेलन-2019 के उपरान्त कई औद्योगिक इकाईयों ने राज्य में अपने उद्योग स्थापित करने में रूचि दिखाई है और इससे लगभग 97 हजार करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित औद्योगिक विकास योजना केवल मार्च, 2022 तक ही प्रभावी है और राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाए।

जय राम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों और पुलों के रख-रखाव और मुरम्मत के लिए विशेष अनुदान प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में राज्य में बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण सड़क आधारभूत संरचना को लगभग 1100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई सहायता को अपर्याप्त बताते हुए उन्होंने कहा कि यह निधि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए भी आवंटित की गई थी।

मुख्यमंत्री ने वेज एंड मीन्स एडवांसिज की सीमा को जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश के राजस्व में आई कमी की क्षतिपूर्ति की जा सकेगी और राज्य में विकास गतिविधियों को भी जारी रखा जा सकेगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. आर.एन. बत्ता भी उपस्थित थे।

177 में से 129 तहसीलें स्थानीय से केंद्रीकृत वेब आधारित प्रणाली में स्थानांतरित

शिमला/शैल। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश ने 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री के मंडी दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में नई परियोजनाओं के उद्घाटन और वस्तुत: नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए भारी मात्रा में उपयोग की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान की। इन परियोजनाओं में शामिल हैं सावरा-कुडडू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, धौलासिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश के डीडीजी और राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी अजय सिंह चहल ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि एनएचएम राज्य के एनएचएम के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण जैसे ऑक्सीजन कंसंटेटर, पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंट्रोलर प्रदान कर रहा है। चहल ने बताया कि पिछले 2 वर्षो से https://oxycare.gov.in पोर्टल का उपयोग करके इन उपकरणों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को संभाला जा रहा है, जिसे एनआईसी द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा, एक और स्वास्थ्य उपकरण यानी ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे समाधान में एकीकृत है और ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीकेयर सॉल्यूशन से उत्पन्न सुरक्षित बारकोड भी है, मोबाइल ऐप का उपयोग करके आसानी से प्राप्त किया जाता है और विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध है जो विभाग को आपूर्ति की निगरानी में मदद करता है। डीडीजी ने बताया कि आक्सीकेयर एमआईएस में 50,000 सिलेंडर ऑनबोर्ड किए गए हैं।

चहल ने कहा कि राज्य में क्लाइंट सर्वर-आधारित समाधान को वेब-आधारित समाधान में बदलने की प्रक्रिया में, भूमि रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकरण भी वेब-आधारित समाधानों में स्थानांतरित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में तहसील/उप-तहसील डेटा को तहसील सर्वर से केंद्रीकृत सर्वर में स्थानांतरित करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 177 में से 129 तहसीलों को स्थानीय से केंद्रीकृत वेब-आधारित प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पूरी प्रणाली के सुचारू क्रियान्वयन में भूमि अभिलेख विभाग ने जिलावार मास्टर ट्रेनर्स को क्षमता निर्माण कार्यक्रम की आवश्यकता बताई। चहल ने कहा कि हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) में 9 और 10 दिसंबर को दो दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन मास्टर प्रशिक्षकों का क्षमता निर्माण किया गया था, जिसमें 72 राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के वीसी सहित लगभग 79 कुलपतियों में चालू माह में कई विभागों के लिए लगभग 700 घंटे के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों की व्यवस्था की गई थी।

पीएम-किसान योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 9.68 लाख पात्र किसानों को 1537 करोड़ रुपये की राशि जारीःजय राम ठाकुर

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

(पीएम-किसान) योजना के अन्तर्गत देश के 10.09 करोड़ किसान परिवारों को दसवीं किस्त के रूप में 20,946 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ जारी किए।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 351 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 14.04 करोड़ रुपये की इक्विटी ग्रांट भी जारी की, जिससे 1.24 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भी शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इसके उपरांत, पत्रकारों से बातचीत में जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल योगदान 13.62 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 88 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसान हैं। प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2021 तक इस महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत 9.68 लाख पात्र किसानों को 1537 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 107 किसान उत्पादक संगठन हैं, जिनके 15 हजार सदस्य हैं। यह किसान उत्पादक संगठन राज्य में विभिन्न कृषि एवं सहायक गतिविधियों में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज प्रदेश के सात किसान उत्पादक संगठनों को 16.72 लाख रुपये की इक्विटी ग्रांट जारी की है।

पी.एम. कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए नामित सरकारी विभाग के माध्यम से ही करें आवेदन

शिमला/शैल। कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सौर पम्पों से सिंचाई के लिए व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर मशीनरी लगाने के लिए लघु सीमांत वर्ग के किसानों को 85 प्रतिशत की सहायता तथा मध्यम व बड़े वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है।

प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में यह आया है कि कुछ फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्लीकेशन प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के नाम पर किसानों से सोलर पम्प लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और पंजीकरण शुल्क तथा पम्प की कीमत का ऑनलाइन भुगतान करने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से निराधार है और आवेदकों तथा जन-साधारण से ऐसी फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्लीकेशन पर क्लिक न करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह फर्जी वेबसाइट जन-साधारण से धोखाधड़ी कर उनके पैसे व आवश्यक जानकारी जुटा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पी.एम. कुसुम योजना सरकार द्वारा केवल प्रदेश के नामित सरकारी विभाग के माध्यम से ही कार्यान्वित की जा रही है तथा लाभार्थी किसान को मनोनीत सरकारी विभाग को ही अपना हिस्सा जमा करवाना होता है। उन्होंने कहा कि नामित विभागों के बारे में तथा अन्य आवश्यक जानकारी जैसे कि भागीदारी के लिए पात्रता व कार्यान्वयन प्रक्रिया इत्यादि के बारे में अधिकारिक जानकारी एम.एन.आर.ई. की वेबसाइट www.mnre.gov.in. पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नम्बर-1800-180-3333 पर सम्पर्क करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर भी इस योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दी सीडी साख सहकारी सभा सीमित गोहर को बैंक में बदलने के लिए राज्य सरकार करेगी हर संभव प्रयासः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले की दी सीडी साख सहकारी सभा सीमित गोहर को बैंक में बदलने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार और आरबीआई से बात कर तकनीकी पेचीदगियों का समाधान तलाशने की दिशा में कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंडी में दी सीडी साख सहकारी सभा सीमित गोहर के 59वें साधारण अधिवेशन के समापन सत्र को बतौर मुख्यातिथि सम्बोधित कर रहे थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि दी सीडी साख सहकारी सभा सीमित गोहर ने मंडी जिले में शानदार काम किया है। 30 जून 1957 को चच्योट डिवेल्पमेंट ब्लॉक सोसाइटी के नाम से आरंभ यह सभा समय के साथ अपने में आवश्यक परिवर्तन लाकर प्रासंगिक बनी रही। वर्तमान में सभा का कुल कारोबार 1500 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सराहनीय है कि लगभग 64 वर्षों के अपने सफर के बाद आज यह सभा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और इसके 66 हजार 298 सदस्य हैं। मंडी जिले में ये अपने सदस्यों को घर द्वार पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसकी 49 शाखाएं और 2 विस्तार पटल हैं। सभा ने 165 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण बांटे हैं। उन्होंने ऋणों की वसूली के मैकेनिज्म की मजबूती पर बल दिया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सहकार बहुत मजबूत सेक्टर है, जिसकी हर जगह पहुंच है। मिलकर काम करने, परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़ने का यह कान्सेप्ट पुराने समय से ही हमारे गांव में मौजूद रहा है। अच्छे-बुरे में साथ रहना, एक-दूसरे के काम में मदद करने का भाव ही सहकार का मूल है, जिसने आगे बढ़कर एक बड़े आंदोलन का रूप लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दी सीडी साख सहकारी सभा सीमित के विस्तार की बहुत सम्भावनाएं हैं। इसकी मंडी जिले से बाहर विस्तार की मांग हो या फिर इस सभा को राज्य सहकारी बैंक में जमा अमानतों पर 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) अधिक ब्याज प्रदान करवाने की बात हो, राज्य सरकार इन मामलों में समाधान का रास्ता तलाशने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने इस अवसर पर सभा की पत्रिका सीडी दर्पण 2021-22 का विमोचन भी किया।

इससे पूर्व, दी सीडी साख सहकारी सभा सीमित के अध्यक्ष कमल राणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें सभा की गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्होंने सहकारी सभा की विभिन्न मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, जिन्हें मुख्यमंत्री ने पूरी गम्भीरता से सुना और हर सम्भव मदद का भरोसा दिया।

इस अवसर पर विधायक राकेश जम्वाल, विनोद कुमार और इंद्र सिंह गांधी, जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री सहित अन्य अधिकारी और सहकारी सभा के सदस्य उपस्थित थे।

जिला कुल्लू की चार पंचायतों में सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि जिला कुल्लू के विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायत जाबन व नम्होग तथा विकास खण्ड नग्गर की ग्राम पंचायत कर्जा एवं सोयल में सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार इन पंचायतों में 30 जनवरी, 2022 को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 11, 12 व 15 जनवरी, 2022 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी जांच पड़ताल 17 जनवरी, 2022 को सम्बन्धित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रातः 10 बजे से करेंगे। इच्छुक प्रत्याशी 19 जनवरी, 2022 को प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापिस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी, 2022 को नामांकन पत्रों की वापिसी के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के तुरंत पश्चात सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के मुख्यालय में मतगणना की जाएगी।

इस अधिसूचना के साथ ही विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायत जाबन व नम्होग तथा विकास खण्ड नग्गर की ग्राम पंचायत कर्जा एवं सोयल में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि इन पंचायतों के किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज न हुआ हो तो वह 6 जनवरी, 2022 तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)-एवं-उपायुक्त को प्रपत्र-2 पर दोहरी प्रति में मात्र 2 रुपये का शुल्क अदा कर प्रस्तुत कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का किया शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रशासनिक सुधार विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का शुभारम्भ किया। हिमाचल प्रदेश इस पोर्टल को आरम्भ करने वाला देश के छोटे राज्यों में प्रथम राज्य और महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बाद चौथा राज्य बना है। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल आरम्भ करने के विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह आमजन को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करने, सूचना प्राप्त करने और अपील करने में सहायक सिद्ध होगा। लोगों को अब उक्त सुविधाएं उनके घर-द्वार पर ही हासिल होंगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस पहल से सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम होगी और लोगों को समय पर सूचना उपलब्ध होगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा, सचिव प्रशासनिक सुधार डॉ. सन्दीप भटनागर, संयुक्त सचिव राजेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

पर्यावरण जिम्मेदारियों पर जागरूकता अभियान

शिमला/शैल। डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) के तहत पर्यावरण जिम्मेदारियों पर एक दिवसीय जागरूकता अभियान का आयोजन किया जिसके बाद परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें 215 छात्रों ने भाग लिया।

पर्यावरण विज्ञान विभाग के हेड प्रो. एस के भारद्वाज ने कहा कि परिसर को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए प्रासंगिक शिक्षा के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रकृति के प्रति भावनात्मक आत्मीयता रखने की आवश्यकता की वकालत की। इस अवसर पर भाषण, स्किट और मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। बीएससी फॉरेस्ट्री की छात्रा प्रियंका शर्मा ने वानिकी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन शमन विषय पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि सूरज, आशीष, रजत, प्रियंका, दर्शन और स्वस्तिक द्वारा तैयार किए गए स्किट- बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन पहले स्थान पर रहा । शहरी कचरा प्रबंधन विषय पर रजत, प्रियंका और स्वस्तिक द्वारा तैयार किया गया मॉडल पहले स्थान पर रहा। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह ने भी छात्रों को वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर व्याख्यान दिया।

पर्यावरण विज्ञान विभाग और स्पेस क्लब के संकाय के साथ बीएससी वानिकी चतुर्थ वर्ष के छात्रों द्वारा एक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। डॉ. केके रैना, प्रधान अन्वेषक, आईडीपी इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे जबकि क्लस्टर विश्वविद्यालय, मंडी की डॉ. ज्योति गुप्ता विशिष्ट अतिथि रही। डॉ. रैना ने छात्रों को उनकी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के बारे में प्रोत्साहित किया और बताया कि आईडीपी के तहत, परिसर को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए कई हरित पहल की गई है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि पारिस्थितिक पदचिह्नों को कम करने के लिए परिसर में ई-कार्ट को क्रियान्वित किया गया है और वृक्षारोपण अभियान नियमित रूप से चलाया जा रहा है। सोलर लाइट लगाई गई है और सोलर रूफटॉप हार्वेस्टिंग भी की गई है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रतिमा वैद्य व डॉ. हुकम चंद शर्मा ने किया।

इग्नू में जनवरी 2022 सत्र के लिए प्रवेश प्रारम्भ

शिमला/शैल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में शैक्षणिक सत्र जनवरी 2022 के लिए विभिन्न मास्टर डिग्री/बैचलर डिग्री/ डिप्लोमा/ पी.जी.डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रवेश प्रारम्भ हो चुके हैं। प्रवेश प्रक्रिया आनलाइन रहेगी जिसके लिए लिंक इग्नू की वैबसाइट www.ignou.ac.in.पर उपलब्ध है।

इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, खलीणी, शिमला के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. जोगिन्दर कुमार यादव ने पीआईबी को बताया कि युनिवर्सिटी जनवरी 2022 सत्र के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रें के लिए बी.ए.,बी.काम,बी.एस.सी. तथा कुछेक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि इग्नू से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र इग्नू की वैबसाइट के माध्यम से प्रवेश के लिए 31 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के किसी भी नजदीकी अध्ययन केन्द्र से या इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, खलीणी, शिमला के दूरभाष संख्या 0177-2624612 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

www.shailsamachar.com

घातक होगी कांग्रेस में उठी शक्ति परीक्षण की कवायद

- सुक्खू समर्थकों के दिल्ली में डेरा डालने से उठी चर्चा
- दो कार्यकारी अधयक्ष और एक सीएलपी उप नेता बनाये जाने की बढ़ी अटकने

शिमला/शैल। मोदी सरकार ने देश की जनता को नये वर्ष पर बहुत सारी चीजों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करके महंगाई का उपहार दिया है। सरकार के इस महंगाई उपहार को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखा हमला किया है। महंगाई से बेरोजगारी भी बढ़ेगी इस पर भी कांग्रेस ने विस्तार से चर्चा की है। महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिन से हर आदमी प्रभावित हो रहा है। हर आदमी इन्हें समझ भी रहा है। लेकिन आज जिस तरह से सरकार और उसके शुभचिंतक इस समस्या के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकारों को दोष देकर राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मथुरा तथा तीन तलाक और धारा 370 के हटाये जाने को सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास बता कर अपना पक्ष रख रहे हैं। उसके कारण आम आदमी महंगाई बेरोजगारी को स्वाभाविक प्रतिफल मानकर अपना तीव्र रोष व्यक्त नहीं कर पा रहा है। जब तक आम आदमी का रोष पूरी तरह मुखर होकर सड़क पर नहीं आ जाता है तब तक सरकार इस पर लगाम लगाने का कोई प्रयास नहीं करेगी।

महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े परोसने के साथ ही कांग्रेस को इसके कारण भी जनता के सामने रखने होंगे। सरकार के कौन से ऐसे फैसले रहे हैं जिन का परिणाम महंगाई के रूप में सामने आया है। कांग्रेस ने नये साल के अवसर पर महंगाई बेरोजगारी को लेकर एक विस्तृत चार पन्नों की प्रतिक्रिया जारी की है लेकिन इसमें इसके कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया से यही संकेत उभरता है कि यह एक रस्म अदायगी मात्र है। जबकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी के ऐसे फैसले उपलब्ध हैं जिनको लेकर सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। हिमाचल सरकार के खिलाफ तो सीएजी ने ही बड़ा फतवा दिया है कि सरकार ने 96 योजनाओं पर एक नया पैसा तक खर्च नहीं किया है। जबकि यह सारी योजनायें जनहित से जुड़ी हुयी है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास से लेकर मंत्रियों अधिकारियों के आवास तक ऐसे कार्यों को अंजाम दिया गया है जिनको शायद नियम भी अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस इन सारे मुद्दों पर खामोश रही है।

भ्रष्टाचार पर तो शांता कुमार ने ही अपनी आत्मकथा में सरकार को बुरी तरह घेरा हुआ है। शांता कुमार के इन आरोपों को यदि प्रदेश कांग्रेस मुद्दा बनाती तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को घेरा जा सकता था। क्योंकि 2014 में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा था जो सत्ता परिवर्तन का कारण बना था। जयराम सरकार के भ्रष्टाचार पर भी कांग्रेस अभी तक पूरी तरह हमलावर होकर सामने नहीं आयी है। बल्कि विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेर पा रही है उन मुद्दों को भी जनता में पूरी ईमानदारी से नहीं रख कर पायी है। जबकि इस समय एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है यह सही है कि प्रदेश की जनता ने उपचुनावों के माध्यम से सरकार को कड़ा संदेश दे दिया है। लेकिन इसमें कांग्रेस की ओर से कोई बड़ा योगदान भी नहीं है।

इस समय कांग्रेस में जिस तरह की खीचातानी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष होने के लिए शुरू होकर बाहर आ गयी है वह कालांतर में पार्टी की सेहत के लिए कोई बड़ा अच्छा संकेत नही है। इस समय अध्यक्ष के साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष के साथ उप नेता बनाये जाने के प्रयासों का आम जनता पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री को सफल माना जा सकता है और उसी तर्ज पर दो नगर निगमों के बाद आये विधानसभा तथा लोकसभा के चारों उपचुनाव जीतना कुलदीप राठौर के पक्ष में जाता है। यह सही है कि इस समय सुक्खू ही एक ऐसे नेता है जो छः वर्ष तक पार्टी का अध्यक्ष रहा है और वह भी स्व. वीरभद्र सिंह के विरोध के बावजूद। इस नाते प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सुक्खू के समर्थक हैं। इस नाते आज प्रदेश के बड़े नेताओं के नाम पर यदि प्रतिभा सिंह, आशा कुमारी, सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर किसी भी कारण से एकजुटता का संदेश न दे पाये तो यह पार्टी के लिए घातक होगा। शक्ति परीक्षण की कोई भी कवायद किसी के भी हक में नहीं होगी अब यह तय है।

क्या आप हिमाचल में स्थान बना पायेगी

- नगर निगम शिमला का चुनाव लड़ने की घोषणा से उठा सवाल

शिमला/शैल। क्या आज आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी कोई सफलता हासिल कर पायेगी। यह सवाल पार्टी के नगर निगम चंडीगढ़ के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने से चर्चा में आ गया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शिमला में अपना कार्यालय स्थापित करके प्रदेश प्रभारी के रूप में भी दिल्ली के एक नेता को यह बिठा दिया है। वैसे तो 2014 के लोकसभा चुनाव से ही प्रदेश की चारों सीटों पर चुनाव लड़कर पार्टी अपना स्थान बनाने में लगी हुई है। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद आज तक पार्टी ने प्रदेश में अधिकारिक रूप से कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है। चंडीगढ़ के चुनाव में भी पार्टी को कांग्रेस भाजपा के मुकाबले सबसे कम वोट प्रतिशत मिला है। इसमें सबसे अधिक वोट शेयर कांग्रेस और दूसरे नम्बर पर भाजपा रही है। इसलिए चंडीगढ़ में मिली आप की सफलता को एक बड़ी जनस्वीकार्यता भी नही माना जा सकता। चंडीगढ़ नगर निगम पर भाजपा का कब्जा था और इन चुनाव में उसके मेयर का भी आप के हाथों हार जाना निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीतिक घटना है। पंजाब में जब से अमरिन्दर कांग्रेस छोड़कर अपनी पंजाब लोक कांग्रेस बनाकर भाजपा के साथ गठबंधन में गये हैं उसके बाद ही चंडीगढ़ के यह चुनाव हुये हैं। ऐसे में इन चुनावों के परिणामों को इस नये गठबंधन के भविष्य के रूप में भी देखा जा रहा है। इसका पंजाब के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

लेकिन इस समय जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश में उभरता जा रहा है उससे यह बात विशेष रूप से सामने आ रही है कि सभी जगह सत्तारूढ़ भाजपा की बजाये कांग्रेस का ज्यादा विरोध किया जा रहा है। जो राजनीतिक दल भाजपा से सत्ता छीनने के दावेदार बन रहे हैं उन सबका पहला विरोध कांग्रेस का हो रहा है। सपा टीएमसी और आम आदमी पार्टी सभी इस कड़ी में शामिल राजनीतिक दल है। जहां जहां भाजपा कमजोर हो रही है उन्हीं राज्यों में यह दल चुनाव लड़ने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस परिपेक्ष में यदि हिमाचल में आप का आकलन किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन उपचुनावों में आप के नेताओं का समर्थन भाजपा के साथ था। बल्कि आप के कई बड़े नेता तो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रीयों के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे थे। अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व नगर निगम शिमला के चुनाव आ रहे हैं। भाजपा भी चारों उपचुनाव हार कर काफी कमजोर हुई है। नगर निगम शिमला में भी भाजपा की स्थिति बहुत नाजुक है इस परिदृश्य में आप ने शिमला नगर निगम के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आप यह चुनाव इमानदारी से भाजपा के खिलाफ लड़ती है या सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिये ही लड़ती है। नगर निगम शिमला में आप का प्रदर्शन उसका प्रदेश में भविष्य तय करेगा।

क्योंकि अभी तक आप की ओर से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसका पहला राजनीतिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस है या भाजपा। आप पूरे देश में दिल्ली मॉडल पर काम करने के दावे कर रही है। जबकि व्यवहारिक पक्ष यह है कि जितना राजस्व दिल्ली सरकार का है उतना किसी और प्रदेश का नहीं है। फिर दिल्ली का आधे से ज्यादा काम नगर निगमों के पास है जिन पर आज भी भाजपा का कब्जा है।